भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1406
उत्तर देने की तारीख: 04.12.2024

अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण और विकास योजनाएं

1406. श्री इमरान मसूद:
श्री राजीव राय:
श्री रमाशंकर राजभर:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कितनी नई कल्याणकारी और विकास योजनाएं शुरू की गई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने में सरकार द्वारा राज्य-वार और अल्पसंख्यक समुदाय-वार कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को राज्य-वार और योजना-वार विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपयोग की गई धनराशि का प्रतिशत क्या है;

(घ) उक्त योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं; और

(ङ) क्या कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में कोई एकरूपता है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

<u>उत्तर</u>

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (ङ): पिछले दस वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अल्पसंख्यक समुदायों के लिए निम्नलिखित नई योजनाएं शुरू की गई हैं:

i) नई मंज़िल योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसे अल्पसंख्यक युवाओं जिनके पास औपचारिक स्कूल ड्रॉपआउट प्रमाण पत्र नहीं है, को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इस योजना ने औपचारिक शिक्षा (कक्षा VIII या X) और कौशल का संयोजन प्रदान किया और लाभार्थियों को बेहतर रोजगार और आजीविका अर्जित करने में सक्षम बनाया। शुरुआत से लेकर अब तक, इस योजना के तहत 98,712 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ii) उस्ताद योजना 2015 में शुरू हुई थी और इसका लक्ष्य मास्टर कारीगरों/शिल्पकारों के पारंपरिक कौशल का निर्माण और उन्नयन करना था। शुरुआत से लेकर अब तक इस योजना के तहत लगभग 21,611 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इन योजनाओं को मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के माध्यम से कार्यान्वयन किया गया। इसलिए, योजनाओं के तहत राज्यवार निधि आवंटन नहीं किया गया।

इन योजनाओं को अब प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) में समायोजित कर दिया गया है। पीएम विकास, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (MoMA) की एक प्रमुख योजना है, जो छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मंत्रालय की पांच पूर्ववर्ती योजनाओं 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'उस्ताद', 'नई रोशनी' और हमारी धरोहर को समायोजित करती है। यह योजना कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमशीलता और नेतृत्व; और स्कूल ड्रॉपआउट छात्रों के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान पर केंद्रित है। पीएम विकास योजना इस साल शुरू की गई थी, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर इसे शुरू नहीं किया गया है।

इसके अलावा, सरकार अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर और कम सुविधा प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए कई अन्य योजनाएं भी लागू करती है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह (6) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए देश भर में विभिन्न योजनाओं को विशेष रूप से लागू करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं/कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. शैक्षिक सशक्तीकरण योजनाएं

i. मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना
ii. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना
iii. मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना

2. रोजगार एवं आर्थिक सशक्तीकरण योजनाएं

i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC): एनएमडीएफसी अधिसूचित अल्पसंख्यकों में से "पिछड़े वर्गों" को संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केनरा बैंक द्वारा नामित राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों (SCA) के माध्यम से सावधि ऋण, शिक्षा ऋण, विरासत योजना और सूक्ष्म वित्त योजना की अपनी योजनाओं के अंतर्गत स्वरोजगार आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती ऋण प्रदान करता है।

3. बुनियादी ढांचा विकास योजना

i) प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK): देश के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केन्द्रित परियोजनाएं, पेयजल एवं आपूर्ति, स्वच्छता और खेल जैसे क्षेत्रों में सामुदायिक बुनियादी ढांचे का विकास करता है।

4. विशेष योजनाएं

जियो पारसी : भारत में पारसियों की जनसंख्या में हो रही गिरावट को बदलने के लिए एक योजना।

इन योजनाओं का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर उपलब्ध है।

सभी योजनाओं ने उच्च स्तरीय कौशल प्राप्ति, आजीविका के बेहतर अवसर, उच्च रोजगार क्षमता, बेहतर बुनियादी ढांचे तक पहुंच, बेहतर स्वास्थ्य और अल्पसंख्यक समुदायों के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।

*****